

केंद्रीय मंत्री आठवले ने हाथरस के डीएम की भूमिका पर उठाया सवाल

जबरिया अंतिम संस्कार पर आपति

लखनऊ, संवाददाता।

केंद्रीय मंत्री आठवले ने ग्रामीण योग्यता के बाबत विवाह संस्कार के बारे में जापन देने पहुंचे तो कुलपति ने मिलने से मना कर दिया जिस प्रकार करने पर कुलपति के सदस्य बृजजय गवत द्वारा काफी अधिकारी की गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग व समाजवादी पार्टी के लिए अपशब्द भी कहे गये, जोकि बहुत निन्दनीय है व यह सवाल भी उठाता है कि जब इस शृंगृत मनसिकता के व्यक्ति विश्वविद्यालय के जिम्मेदार परों पर होंगे तो किस तरह की शिक्षा विश्वविद्यालय में मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री आठवले ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद योजना भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाथरस की घटना में बेहद गंभीर घटना है। इसमें उत्तर प्रदेश सकार जांच करा रही है। इस घटना में सरकार को पीड़ित परिवार की बजाए विवाही दलों का नामों टेस्ट कराना चाहिए। आठवले ने कहा कि दलित उत्तर प्रदेश सकार जांच करा रही है। यह राजनीति नहीं होना चाहिए। यह कहना गलत है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। दलित उत्तर प्रदेश की सरकार में भी अत्याचार होते थे। उत्तरोंने कहा कि

चाहिए। सबकी सरकार में दलित अत्याचार हुए। इसमें पहले उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार में भी अत्याचार होता था। उत्तरोंने जिलाधिकारी के खिलाफ कहा कि किसी की भी बालिका या किसी का भी जबरन अंतिम संस्कार गलत है। यह बेहद गंभीर बात है। उत्तरोंने जिलाधिकारी के खिलाफ कहा कि इस मामले में चारों

मायावती इस मुदे पर बेहद घटिया राजनीति कर रहा है। उत्तर सो-एम योगी आदित्यनाथ से शिरीफे की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। आठवले ने कहा कि जब तक हमरे दलितों के साथ अत्याचार होता रहेगा। उत्तरोंने कहा कि अंतर्राजातीय विवाह से समाज में बदलाव आया।

केंद्रीय मंत्री ने हाथरस के इस कांड में जिलाधिकारी प्रीती कमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उत्तरोंने कहा कि जिलाधिकारी ने घटना को लेकर गहुल का साथ निशाना। गहुल गांधी हाथरस के लिए आए, लेकिन राजस्थान नहीं गए। राजस्थान में उनकी सरकार है। राहुल को अगर पुलिस ने रोका था तो रुकना चाहिए। उत्तरोंने पुलिस से धक्का मुक्की की, जिससे बह गिरे, उत्तरोंने पुलिस ने नहीं गिराया।

आरोपितों को फांसी होनी चाहिए। हाथरस की घटना मानवता पर एक धब्बा है। इस मामले में पीड़ित परिवार को घटना करने का अधिकार नहीं है। आठवले ने कहा कि जब तक हमरे दलितों के साथ अत्याचार होता रहेगा। उत्तरोंने कहा कि अंतर्राजातीय विवाह से समाज में बदलाव आया।

कल मैं हाथरस जाने वाला था लेकिन प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने नहीं दिया जा रहा। आठवले ने हाथरस की घटना को लेकर गहुल का साथ निशाना। गहुल गांधी हाथरस के लिए आए, लेकिन राजस्थान नहीं गए। राजस्थान में उनकी सरकार है। राहुल को अगर पुलिस ने रोका था तो रुकना चाहिए। उत्तरोंने पुलिस से धक्का मुक्की की, जिससे बह गिरे, उत्तरोंने पुलिस ने नहीं गिराया।

डीएम हाथरस के निलंबन हेतु हस्तक्षेप करे आईपीएस एसोसियेशन

लखनऊ, संवाददाता। आईपीएस अध्यक्ष अनिताम गवर ने यूपी आईपीएस एसोसियेशन को हाथरस में एपीपी विकास ने व पुलिस आपारों के निलंबन के लिए गहुल में डीएम हाथरस कुमार लक्ष्मण को निलंबित किया जाने की मांग की है। यूपी एसोसियेशन तथा सेंट्रल आईपीएस एसोसियेशन को भेजे गए ने अविभावनी ने कहा कि पुलिस आपारों पर कार्रवाई अपेक्षित थी, किंतु यह सच यही इस मामले में डीएम हाथरस के खिलाफी अतिरिक्त तथा निश्चित व सोशल मीडिया से साजना आ रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों के परिवार को धमकी देने जैसे गंभीर आपत्ति देने का अनुभव आया है। उत्तरोंने आईपीएस एसोसियेशन को इन तथ्यों को शासन को अवगत कराए हुए विभिन्न सेवाओं में समानाता एवं न्याय के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार गौजुला डीएम हाथरस के विरुद्ध भी जिलाधिकारी अतिरिक्त तथा निश्चित व सोशल मीडिया से साजना आ रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों के परिवार को धमकी देने जैसे गंभीर आपत्ति देने का अनुभव आया है।

हाथरस नार्को टेस्ट निर्णय सुप्रीम कोर्ट आदेश के विरुद्ध, अस्वैधानिक

लखनऊ, संवाददाता। पीटिंग दौरान गहुल ने हाथरस एप केस में जार प्रदेश सरकार द्वारा प्रिया पीड़ित के परिवार को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने नहीं दिया जा रहा। आठवले ने हाथरस की घटना को लेकर गहुल का साथ निशाना। गहुल गांधी हाथरस के लिए आए, लेकिन राजस्थान नहीं गए। राजस्थान में उनकी सरकार है। राहुल को अगर पुलिस ने रोका था तो रुकना चाहिए। उत्तरोंने पुलिस से धक्का मुक्की की, जिससे बह गिरे, उत्तरोंने पुलिस ने नहीं गिराया।

लखनऊ, संवाददाता। एपिटिंग दौरान प्रासाद की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने नहीं दिया जा रहा। उत्तरोंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसी एवं अन्य विवाह से बताया गया कि अंतर्राजातीय विवाह से समाज में बदलाव आया।

पीड़ितों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप्त होती है।

पीड़ितों के परिवारों को घटना की तरफ से बताया गया कि अप्पी मिलने वाली सुविधाओं से मान्यता प्राप

आगे कथा? मरुरा और काशी

हूं 20 लाख जीवनों का एक कपड़ा है। मरिंजट शब्द लिखने से बचता रहा। टीवी चैनलों हम सब उसे ढांचा बोलते या प्रिय बाबी। सोशल मीडिया पर भी वही हो रहा था। बाबी बोलो, या ढांचा। परहेज करो, मरिंजट मत बोलो। जब कभी हम इस परहेज की परिधि से बाहर निकलते और बाबी मरिंजट बोल जाते, तुरंत आशेप की बाढ़ आने लगती। मुझे के पक्षकार हो, या पाकिस्तानी? और जो गवात ने पाकिस्तान के कराची में पैदा हुआ, बहुसंख्यक हिंदू मुल्क की राजनीति में बैठेसियत नंबर टू था, उसने 30 सितंबर 2020 को देश की जनता को संबोधित पत्र में बाबी मरिंजट लिखने का साहस कर दिया। जी हाँ, मैं लालकृष्ण आडवाणी की बात कर रहा हूं। वो अपने पत्र में मरिंजट लिखने का साहस कर चुके थे, नगर मरिंजट तोड़ने में अपनी शिरकत को खुलकर कहने का दुर्साहस नहीं कर पाये। 92 साल के लालकृष्ण आडवाणी सनेत बना वो 32 जीवित आरोपी जी कायर निकले? स्पेशल जज सुनेंद्र कुमार यादव से एक रुपये का गुमाना ही मांग लिया होता,

जुकांगन ने जिनेय कटियार को 1974
जानता हूं, जब वे बिहार ने जेपी
आंदोलन के कानिंहर हुआ करते थे।
जेपी से जुड़ने से पहले वे यूपी ने अधिक
भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन
संचित थे। विनय कटियार जेपी से
विमुख हुए, उसके बाद 1980 तक संघ
के प्रधारक रहे।

1982 में हिंदू जागरण म
की स्थापना की, और 1984 में बजरंग
दल की बुनियाद रखी। यों, यह शोध व
विषय है कि जेपी और अबा के कितने
अनुयायी इस समय भगवा राजनीति में
हैं? वर्तमान में विनय कटियार बीजेपी
में हैं। यूपी से पांच बार सांसद रहे विनय
कटियार जो बयान दे रहे हैं, क्या उसे
बीजेपी का आधिकारिक वक्तव्य माना
जाए? 30 सितंबर 2020 को सीबीआई
की विशेष अदालत के फैसले के बाद
बयानों की जो झड़ी लगी, उसमें विनय
कटियार का थोड़ा हटकर दिया वक्तव्य
भावी योजनाओं की ओर इशारा कर रहा
था। तब विनय कटियार ने स्पष्ट कहा
था कि अब मथुरा और काशी की तैयारी
होगी। सभी साधु-सत गिलकर तय

कहने के काम आता जा सकता है। अंदोलन को आगे लेकर जाना है। मगर, क्या विनय कटियार की इस मत्ता से स्वयं पीएम मोदी, या राष्ट्रीय स्वरांशेषक संघ सहमत है? राम मत्ता अंदोलन की अदालती सुनवाई में ऐसे कई अवसर आये, जब पीएम मोदी से विनय कटियार की असहमतियां दिए पीएम मोदी काशी से सांसद भी हैं, इसलिए उनकी स्थानीय जिन्मेदारी न हो जाती। देश जानना चाहेगा कि वो ज्ञानवापी महिंद्र के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, या नहीं? पीएम मनोज काशी विश्वनाथ कॉर्टीडोर का जो ग्राहिक अपने आधिकारिक पोस्ट पर डाली है, उसमें ज्ञानवापी महिंद्र स्पष्ट रूप से उकेरा दियाया गया है। ज्ञानवापी महिंद्र या मथुरा का शार्ह ईदगाह महिंद्र, शबाबीय की तरह ढांचा भर नहीं है। इन महिंदों में नमाज अदा की जाती है। ज्ञानवापी के प्रबंधन का काम देखने वाले अंग्रेजों इतोजामिया महिंद्र के महासंघिव एस.एम. यासीन बोलते हैं कि कॉर्टीडोर के निर्माण से हमारे समुदाय पर को

जल्दी जाने पड़ा है, जोतीजप सूक्ष्मता सुरक्षित है, फिर भी डर तो लगा सकता है। काशी विश्वनाथ कॉर्टीडोर प्रधानमंत्री की सर्वाधिक प्रिय परियोजना से एक है। मोटी की महत्वाकांशी विश्वनाथ कॉर्टीडोर पर लगातार काश चल रहा है, जिसपर 600 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस कॉर्टीडोर जून 2021 तक पूरा कर दिये जाने की लक्ष्य रखा गया है। इस ध्यान में की आवश्यकता है कि बाबरी मस्जिद विवाद से पहले काशी में ज्ञानवापी लेकर बारेला मचा हुआ था। उसे देख के वास्ते पीवी नरसिंहराव सरकार 1991 में पूजा स्थल संरक्षण कानून बनाया था। उस कघनक का उद्देश्य यही था कि विश्व हिंदू परिषद् व अस्त्र हिंदू संगठनों को ज्ञानवापी और शहीदगाह मस्जिद को निशाने पर ले रोका जाए। इस कघनक के पास ही जाने के बाद भी धार्मिक संगठन इन नहीं हुए। 1991 में काशी-विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (केवीटी) और स्वर्यंग भगवान शिव की ओर से वाराणसी के अदालत में अंगुजन इतेजामिया म

क दिवंगु जापका विवर का गया। जग्नीन मटिर को सौंपी जाए, जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर मस्तिष्क बनाया। औरंगजेब के समय भी इसका नाम ज्ञानवापी ही रहने दिया। एक अंग्रेज विशेष ऐजेनाल बैबल 1824 में ज्ञानवापी का दौरा किया। उसने अपने संस्मरण में लिखा— मटिर परिसर में एक प्राचीन कुट्टा नाम था ज्ञानवापी, जिसे भक्त गंगा से नी पवित्र मानते थे। शुभ वाराणसी सिटी गाइडशै दे पेज 9 में लिखा है कि पुजारियों का विश्वास उस कुएं में लिंगम अवधितथा था। इसलिए मूल मटिर उसी स्थल पर जिसका विध्वंस कर औरंगजेब ने मस्तिष्क बनवाया था।

1909 में लंदन मिस्र सोसाइटी से जुड़े एकिविन ग्रीष्म वात्रा वृतात क्षाक्षी द सिटी इलेक्ट्रिक के पेज 80 में लिखा कि मैं उस पर गया और मस्तिष्क के भीतर स्तंभ देखे, जो काफ़ी प्राचीन लग ये तथ्य ज्ञानवापी विवाद के 167 82 साल पहले ऋमशरूद दो अल-

जैतान राजका ने दिया। आठवें अंक का वर्जन से सिर्फ़काली का धर्मस्थल विवादित नहीं है। उसने मथुरा में भी ऐसा ही बोया था। मथुरा में शाही ईदगाह मसिजिद कृष्ण की जन्मभूमि मनिर परिसर के बगल में अवस्थित है, जिसे भगवान् कृष्ण का जन्मस्थल माना जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने 1670 के आसपास 13.37 एकड़ में बने प्राचीन कट्टा केरावदेव मनिर को तुड़वाकर मसिजिद का निर्माण करवाया था। मगर, शतार्दीखे दाउदीशु में मुगल बादशाह जहांगीर ने जिक्र किया है कि सोलहवीं सदी में दिल्ली सल्तनत के सुलतान सिकंदर लोदी ने मथुरा के मनिरों का विवेष किया था। मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले जफ़राब गिलानी बताते हैं कि 1968 में शाही ईदगाह मसिजिद समिति व कृष्ण भूमि ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ था, और मसिजिद के प्रबंधन का अधिकार मुस्लिम समिति को सौंप दिया गया था। बाबरी मसिजिद विवेष के छह माह बाद वृद्धावन निवासी मनोहरलाल शर्मा ने 1968 में हुए समझौते को रद करने के बाद ने बुला जाया। जाहाज़ा जो बोयका दायर की। साथ ही 1991 में बने पूजा स्थल संरक्षण कानून को भी चुनौती दी गई। इस अदालती लाझाई का किंच्चसा कोताह यह है कि 28 साल बाद उसी मथुरा जिला अदालत ने बुधवार 30 सितंबर के दिन इस केस को खारिज कर दिया। इसे बिंबाना ही कहिए, भला समृद्धाय एक तरफ़विरोध अदालत ने विजय पर लहू बांट राखा था, पर उसी दिन मथुरा की अदालत में पराजय पर गौन धारण किये हुए था। मगर, यह इस कहानी का द एंड नहीं है। श्रीकृष्ण विश्वगामी की जमीन पाने के वास्ते ये लोग ऊपरी अदालत ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वर्कफ़ोर्ड व शाही ईदगाह ट्रस्ट प्रबंध समिति के विरुद्ध अपील करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि 12 जून 2020 को पूजा स्थल संरक्षण कानून 1991 को एक हिंदू संगठन, विश्व भट्ट पुजारी पुरोहित महासंघश ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हिंदू संगठन मथुरा-काशी विवाद छेड़ने से पहले पूजा स्थल संरक्षण कानून 1991 को जैसे भी निरस्त कराना चाहेंगे।

उत्तरप्रदेश की सत्ता की चाकड़ी में लगी पुलिस

लापरवाहा स काफ आग निकलकर सवदनहनता के दायर का पार करता हुई खुलकर सत्ता की चाकरी करने तक पहुंच गई है। हाथरस की घटना का वर्णन पढ़-सुनकर ही किसी भी संवेदनशील इंसान के रोंगें खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह से अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को शायद धार्मिक भावनाओं के अलावा कोई और भावना समझ ही नहीं आती है। एक वक्त था जब यूपीए के कार्यकाल में हुई घटनाओं पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी सड़कों पर जनता की जुझारू प्रतिनिधि के अभिनय में नजर आती थीं। लेकिन अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के बावजूद उहें हाथरस मामले में दो शब्द कहने में दो दिन लग गए। उन्होंने कहा कि दोषी जल्द फसी पर लटकेगे। इसी तरह उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अदित्यनाथ योगी ने भी दोषियों को सख्त सख्त सजा देने की बात कही है। मगर अभी जिस तरह का रवैया पुलिस का है, उसे देखकर डर लग रहा है कि कहीं उस दलित युवती के साथ किस तरह का दुराचार हुआ, इसकी सही जानकारी कानूनन दर्ज होगी भी या नहीं। सजा तो दोषियों को तभी मिलेगी, जब उन पर जुर्म साबित होगा। 14 सितंबर को हुई इस घटना में 29 सितंबर तक तीन बार पुलिस ने एफआईआर की धाराओं को बदला। पहले केवल हत्या के प्रयास की बात दर्ज हुई, फिर गैंगरेप की और अब पीड़िता की मौत के बाद हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। लड़की ने अस्पताल में दिए अपने बयान में गैंगरेप की बात कही थी, लेकिन पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे बढ़ती है और उसमें अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि गैंगरेप हुआ था या नहीं। दरअसल लड़की मां को जिस हाल में मिली थी, उसमें उसे बड़ी मुश्किल से बगहला के सरकारी अस्पताल तक ले जाया गया था। यहां उसका मेडिको लीगल नहीं किया जा सका, क्योंकि उसकी हालत बेहद

बहस
नहीं
ते हुए
लोग
स्थिति
की
भले
ही भी
दिखें।
ददवार
की
डिक्टेट
बाइडेन
नहीं
अपनी
बलाई,
ते रहे
भाव-
पहले
एक-
रह था
ले तो
जैसमें

बैडर गिन्सबर्ग की मजूरी दी गई
ट्रम्प ने कहा- शम्मै आपको सीधे त
पर बतला देता हूँ कि हम चुनाव जं
चुके हैं। हमारे पास सीनेट है, हमारे प
एक जबर्दस्त प्रत्याशी है जिसका ब
अकादमिक विद्वान सम्मान क
है। बहस में शयद पहली ब
शुरुआत में ट्रम्प शान्त और ध्य
लगाये दिखे जब नीति के सार तर
को लेकर वे तर्क दे रहे थे। इस प
को लेकर वे और बाइडेन आरभ्य
ही भिड़ गये थे लेकिन इसके पह
कि लहर उनकी ओर आती, बाइडेन
सफलतापूर्वक मसले को स्वास्थ
सेवाओं की ओर मोड़ने में कामय
हो गये। बाइडेन ने दावा किया
ट्रम्प द्वारा सुप्रीम कोर्ट की नामांवित
एमी कॉनी बैरेट ओबामा केर
असंवेद्यानिक घोषित कर देंगी। इ
बाइडेन का मजबूत दावा था जिस
उहोंने जल्दी ही बहस की धुरी ब
लिया जिसे कई लोग ओबामा क

सफलताओं का प्रचारित करना उनका पहला मजबूत बिन्दु था। जब ट्रम्प ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बाइडेन को दबाना चाहा तो बाइडेन ने अपनी बन्दूक की नाल को ट्रम्प के चार साल तक पद पर रहने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी योजनाओं के अभाव की ओर तान दिया। दूसरे पक्ष को खराब बयानबाजी के लिये मजबूर करने की रणनीति दोनों की ही नजर आई, और इस मामले में बाइडेन ने तब पहली बढ़त ले ली जब ट्रम्प ने दावा किया कि वे दवाओं की कीमतें 80-90 फीसदी तक कम कर सकेंगे। इस पर बाइडेन ने राष्ट्रपति के पास ठेस योजना के अभाव की बात कहकर उन पर दोहरा हमला बोला। बाइडेन ने कहा- उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई योजना नहीं है। वे केवल खयाली पुलाव पकाते हैं यह उनके पास कार्यकारी निर्देश हैं पर उनमें शक्ति नहीं है। उन्होंने किसी के लिये

जिला

हो उनके पास कुछ नहीं है- उनके पास इसकी कोई योजना नहीं है। सच तो यह है कि इस व्यक्ति को यह मालमत ही नहीं रहता कि वे क्या बोल रहे हैं। जब तक बहस कोविड-19 पर जारी रही, बाइडेन ट्रम्प के रिकार्ड पर दबाव डालते रहे जिसमें उहोने उन लोक हुए टेपों को याद किया जिसमें सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने के काफ़ी पहले राष्ट्रपति यह जानते हुए पाये गये हैं कि संक्रमण काफ़ी खतरनाक है। बाद में, जब विषय मास्क के असर पर चला गया, बाइडेन लगातार ट्रम्प को ठेलते रहे परन्तु इस बार उहें आर्थिक सफलता ही मिली। इस मुद्दे पर ट्रम्प के रिकार्ड से डिबेट के इस हिस्से में उनकी निश्चित जीत के अवसर थे लेकिन बाइडेन इस विषय पर कुछ अंक बटोर लेने की क्षमता के अभाव से वे जितना बच सकते थे उतना बच गये। बाइडेन ने दो लाख अमेरिकियों की कोविड संबंधी मौतों पर तो ध्यान खोया हुआ अवसर था। ट्रम्प अधिक प्रतिबद्धता दिखा गये और अपने प्रमुख मुद्दों से एक पर जोर देने में भी कामयाब रहे। मिर भी, बाइडेन की तरह कोरोना पर ट्रम्प इसे पर्याप्त नहीं भुना पाए। बाइडेन ट्रम्प की ओर से आने वाले हमलों को झेलने में कामयाब रहे, जिन्होंने दावा किया कि वे कानून प्रवर्तन बजट को घटाएंगे और वे कानून-व्यवस्था के खिलाफ हैं। बाइडेन ने कहा-हाँ, मैं कानून-व्यवस्था के पक्ष में हूं और नायक के साथ कानून व व्यवस्था, जिसमें लोगों के साथ निष्पक्षता बरती जाए। ट्रम्प की कानून-व्यवस्था की अवधारणा को काटने और पोर्टलैंड जैसे शहरों में दरों के अर्थ बदलने से लेकर नस्ल संबंधी मामलों की ओर मोड़ने की बाइडेन की क्षमता थी, जिसमें उहें स्पष्ट बढ़त थी। वहां से जब वह आगला विषय बना तो निरुसदैह ट्रम्प ने उस रात की सबसे बड़ी गलती कर दी।

2 अक्टूबर, 2019 से प्रारम्भ होकर 2 अक्टूबर, 2020 को समाप्त हो रहे अपने 150वें जयन्ती वर्ष के दौरान स्वयं महात्मा गांधी और अनेक तरह के घटनाक्रमों ने देशवासियों के आंदोलन व आजाद भारत की कार्य योजना का हिस्सा थे। आजाद भारत के प्रारंभिक वर्षों को छोड़ दें, तो देश गांधीवादी आदर्शों से विभिन्न अवसरों पर छोटे-बड़े कई य टर्न में वृद्धि दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज का अपराधीकरण अलग गुल खिला रहा है। सबसे अधिक चिंतनीय तो यह है कि सामुदायिक-जातिगत संघर्षों से लेकर अपराधों के निर्धारण भी की बेटी के बलात्कार व मौत के बाद जिस तरह से आनन-फनन में उसका रात को अंतिम संस्कार किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि समाज और सरकार के राजनैतिक परिकल्पना में बहुसंख्यकवाद का कोई स्थान नहीं रहा है परन्तु हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, उसमें सारा कुछ बहुसंख्यक लोगों द्वारा और उनके लिए निर्धारित गुरुबत और कष्टप्रद दुनिया की डिजाइन के अलावा कुछ निकलकर नहीं आया है। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर मनव्य के गैरव की रक्षा करने वाला

सामने अपनी पसंद व प्रवृत्तियों के अनुसार भावी मार्ग अपनाने की स्वतंत्रता दे दी है। इसके बाद भारत गांधीजी के नाम पर जब 200वां जयन्ती वर्ष मनाएगा, तब तक दुनिया काफ़ी कुछ बदल चुकी होगी। शरीरिक रूप से सात दशक पूर्व मारे गये गांधी के आदर्शों और मूल्यों को भी मारने के अनेक प्रयास हुए हैं, पर इस एक साल के दौरान हुए उपक्रम कहीं ज्यादा बड़े, सघन और सायास रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि इसी दौरान गांधी को नये सिरे से समझने की भी कोशिशें भी हुई हैं। कुल जमा कह सकते हैं, कि यह एक साल गांधी को मारने और जिलाने दोनों ही तरह के प्रयासों का वर्ष रहा है। जयन्ती वर्ष पर देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां उसका यह निर्णय ही तय करेगा कि आधी शताब्दी के बाद का भारत कैसा होगा। गांधी को मरता हुआ छोड़ देना है या उसको गिरने से थामना है? यही आज का टू बी और नॉट टू बी है। हमने गांधी को आज बचाया तो आधी सदी के बाद का समाज नैतिकता और मानवतावादी मूल्यों पर आधारित समाज होगाय और अगर उसे तड़पते हुए छोड़ जाते हैं, तो...! शुरुआत करें तो, पिछले साल इसी दिन देश ने जिस श्रद्धा के साथ गांधी को याद किया था, उससे आस बंध चली थी कि जनता और सरकार मिलकर समाज को उन मूल्यों की राह पर ले चलेंगे जो गांधी ने भी उन्हें लाए थाएँ।

पिछले दो वर्षों में तो जाति, सम्प्रदाय, राजनीतिक दल, राज्य और सरकार को देखकर हो रहा है। गांधी जयन्ती वर्ष का समापन बाबरी विध्वंस संबंधी न्यायिक फैसले और एक लड़की के बलात्कार से उपजी परिस्थितियों में हो रहा है। 28 वर्ष पूर्व बाबरी मस्जिद को गिराने से देश में जो साम्राज्यिक द्वेष फैला था, वह देश की उदार संस्कृति के कारण काफी कुछ समाप्त तो हो गया परन्तु इसे अवैधानिक कृत्य मानने के बावजूद सभी दोषियों को मुक्त कर देना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कम ही करता है। आगर मस्जिद गिरने से देश के सामाजिक ताने-बाने को धक्का पहुंचा था, तो इस पर आये फैसले ने हमारी न्यायपालिका की चूले ही हिला दी हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के हाथरस की एक युवती की बलात्कार कर जिस नृशंसता से हत्या हुई है, उसने समाज की कार्यप्रणाली पर ही सबाल खड़े कर दिये हैं। न्यायपालिका की इस मामले में पहले ही विश्वसनीयता समाप्तप्राय है। रसूखदार बलात्कारियों को जमानतें और पीड़िताओं को सत्ता की शह पर प्रताड़ित कर हम क्या वैसा समाज रच रहे हैं, जैसा बनाने की कसमें हमारे सत्ताधीश हर 2 अक्टूबर एवं 30 जनवरी को खाया करते हैं? गांधी ने हिंसा से पूर्णतर मुक्त भारत का स्वप्न देखा था, जो ये भी मानते थे कि हिंसा का सबसे ज्यादा खामियाजा समाज का विचार नहीं था। उसकी

क्रियान्वित किया जा रहा है। सामाजिक और वैचारिक रूप से अल्पसंख्यक होते समुदायों के हाथों से यह व्यवस्था सारा कुछ छीन लेना चाहती है। इस प्रयास में जहां हमारे साम्प्रदायिक सौहार्द को आघात पहुंचा है वहीं वैचारिक विविधता, समन्वय और सर्वस्पर्शी भावनाओं का तेजी से विसर्जन हुआ है जो एकांगी समाज की रचना करेगा। गांधीवाद और विपक्ष के सफाए की हसरतों को पूरा करने के लिए सत्ता देश के श्रेष्ठतम सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक तत्वों को ही पलीता लगा रही है, जिसका मोल शायद हम उनके तिरोहित हो जाने के बाद समझ सकेंगे। आखिरकार ये तत्व तो गांधी ने इसी देश की माटी से उठाए हैं। जयन्ती वर्ष के समाप्ति पर यह हमें ही तय करना है कि हम गांधी को मार दें या उन्हें जिलाये रखें। गांधी का खाता करने के पूर्व यह भी सोचना होगा कि दुनिया ने लगभग सभी तरह के राजनैतिक सिद्धांतों, सामाजिक दर्शनों एवं अधिक डॉक्टरीन्स को आजमाकर देख लिया है। इन सभी का उद्देश्य भौतिक विकास करने से ज्यादा कुछ भी नहीं रहा है। इनमें से किसी के भी पास हर तरह की गैरबराबरी दूर करने और सर्वोदय के महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई योजना नहीं है। इनमें एक तरफ मुश्ती भर लोगों की बजबजाती सम्पत्ता और दूसरी ओर अधिकांशों ने तिए एक ऐसा समाज किस प्रकार बनाया जाए जो न केवल सबके लिए एक सी न्यायपूर्ण भावना से चमचमाता हो, जिसकी बुनियाद में मानवतावाद हो और जिसके स्तंभों पर नैतिकता की नकाशी हो। वहां आपको एक दिशा में केवल गांधी और दूसरी दिशा में अन्य कोई भी नजर नहीं आयेगा। हमारे नेता विदेश में गांधीवाद के देश से आये हुए मेहमानों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन विश्व को गांधीवादी चेतना देने के पहले हमें उनके आलोक से खुद को प्रकाशित करना होगा। बुद्ध के बाद भारत के पास दुनिया को देने के लिए अगर आज कुछ भी बचा हुआ है, तो वह सिर्फ गांधी ही है। ऐसे वक्त में गांधी जयन्ती वर्ष का समाप्ति हो रहा है जब देश की सारी संस्थाएं सत्ता के सामने सिर नवा रही हैं, तो प्रतिरोध की प्रेरणा, ऊर्जा और शैली का प्रदाय तो गांधी बाबा ही करेंगे। अपने जीवन को स्वाहा कर बापू ने यह देश संवारा है और हमें सौंपा है। बापू प्रदत्त मूल्य सरकारों को काबिज करने उन्हें चलाने का दिशानिर्देश मात्र कभी नहीं रहे बल्कि वे समग्र मानवीयता के प्रकाश स्तम्भ हैं। गांधी इंतजार कर सकते हैं, पर मानवीयता नहीं। गांधी को बचाना मनुष्यता के बुनियादी तत्वों को बचाये रखना है। महात्माजी को शुग बायश करने के साथ 200वें वर्ष में उन्हें एक बेतरताव देश, बेहतर समाज और एक बेहतर इंसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का संकल्प लेना चाहिए।

